25.08 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक समन्वित परियोजना को अनमोदित किया गया है । इसमें से 11.71 करोड़ रुपए केंद्रीय सरकार द्वारा अपनी 8.91 करोड़ रुपये यूनिसेफ द्वारा, 3.91 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा अपनी निजी निधियों में से वहन किए जायेंगे और शेष 0.55 करोड़ रुपये लाभार्थियों के योगदान से प्राप्त किए जायेंगे । इस परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में रिलीज किए जा चुके हैं।

गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाना

4024. **श्री राघव जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 फरवरी, 1992 की स्थिती के अनुसार ऐसे गांवों की राज्य वार संख्या कितनी है जितनी संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार एक हजार थी लेकिन पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हुए थे ;

(ख) क्या देश में सड़कों के असंतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त गांवों को प्राथमिकता के आधार पर सड़कों से जोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, और

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी, और यदि, नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार, एक हजार और उससे अधिक लोगों की आबादी वाले गांवों की राज्यवार संख्या के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक एक हजार और उससे अधिक की आबादी वाले गांवों, जिन्हें पक्की सड़कों से जोड़ा नहीं गया है, की संख्या के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । सड़कों का निर्माण, जिनमें ग्रामीण सड़कें भी शामिल हैं, राज्य का विषय हैं और इसके लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य योजनाओं में निधियां उपलब्ध कराई जाती ।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सातवीं योजना के अंत तक 1000 और उससे अधिक की आबादी वाले गांवों की संख्या जिन्हे पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है।
1. आंध्र प्रदेश	2286
2. अरुणाचल प्रदेश	13
3. असम	40
4. बिहार	6182
5. गोआ	—
6. गुजरात	406
7. हरियाणा	1
8. हिमाचल प्रदेश	70
9. जम्मू व कश्मीर	174
10. कर्नाटक	2202
11. केरल	—
12. मध्य प्रदेश	2680
13. महाराष्ट्र	864
14. मणिपुर	—
15. मेघालय	—
16. मिजोरम	1
17. नागालैंड	16
18. उड़ीसा	1034
19. पंजाब	—
20. राजस्थान	1147
21. सिक्किम	9
22. तमिलनाडु	561
23. त्रिपुरा	83
24. उत्तर प्रदेश	5360
25. पश्चिम बंगाल	4022
26. अन्डमान निकोबार द्वीप समूह	—
27. चंडीगढ़	—
28. दादर व नागर हवेली	4
29. दमन व दीव	—
30. दिल्ली	—
31. लक्षद्वीप	—
32. पांडिचेरी	—